

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 185/17

दायरा दिनांक 15.09.2017

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

चतरसिंह पुत्र जीवनलाल जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) - अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार शाहबाद

- रेस्पोंस्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

उपरिष्ठत :-

1. अभिभाषक प्रार्थी - वीरेन्द्र अग्रवाल, अजय अगवाल।
2. अभिभाषक अप्रार्थी- एक्स पार्टी।

निर्णय

दिनांक :- 31-7-2019

अपीलान्त निम्न आधारों पर यह अपील पेश करता है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को सर्वथा गलत तौर पर ग्राम मुण्डियर की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा किस्म बंजड भूमि साल 2073 का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 19.05.2017 को अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्त उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत कर रहा है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को विना किसी सूचना के अपीलान्त के विरुद्ध अपीलान्त की गैर हाजरी में अपीलान्त को जबाब सुनवाई का कोई अवसर दिये विना प्रश्नगत निर्णय पारित किया है सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19/05/2017 को पत्रावली पर अपीलान्त को विवादित आराजी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई प्रमाणित साक्ष्य न होने के बाद भी सर्वथा गलत तौर पर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्त ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी नहीं किया है। अपीलान्त एक छोटे से गांव का खेतीहर मजदूर है जिसका पूर्वजों के समय का मकान बना हुआ है। जिसमें अपीलान्त के पास ग्राम मुण्डियर या अन्य किसी स्थान पर कोई मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्त अपने जन्म के समय से निवास करता चला रहा है इस मकान के अलावा अपीलान्त के पास ग्राम मुण्डियर या अन्य किसी भी स्थान पर कोई मकान नहीं है अपीलान्त का मकान स्कूल एवं रोड से करीब 200 फुट दूर अपीलान्त के मकान के आगे की खाली जगह पर गांव के कुछ अरसदार लोग कब्जा करना चाहते हैं और वह लोग पटवारी हल्का से अपीलान्त के विरुद्ध गलत रिपोर्ट करवा रहे हैं। यदि अपीलान्त का मकान या उसका कोई हिस्सा ख.नं. 2 की बंजड भूमि में आ रहा है। तो अपीलान्त लम्बे कब्जे के आधार पर विवादित जगह को नियमन कराने का हकदार है सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानून बिन्दुओं निर्णय पूर्व कोई ध्यान नहीं दिया है और पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलान्त आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व मौका न ही देखा न ही कोई स्वतन्त्र साक्ष्य ली मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवाली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा मनमाने तौर पर पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर विना किसी जांच के अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। प्रश्नगत निर्णय की अपीलान्त को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.09.2017 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की धमकी देने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी का उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होने के बाद प्रार्थी ने नकल निर्णय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 13.09.2017 का नकल मिलने पर यह अपील प्रस्तुत है

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 1208/17 निर्णय दिनांक 19.05.17 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा किस्म बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 800/- रुपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं, साथ ही अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

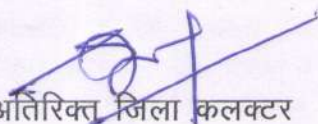
वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ ही अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा पर मकान बना हुआ है। ट्यूवबैल लगी हुई है। रास्ता अवरुद्ध नहीं है। पटवारी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बाबत कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्त द्वारा रोड के समीप व स्कूल के रास्ते के समीप अतिक्रमण कर रखा है।

पत्रावली के अवलोकन व बहस अभिभाषकगण सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्त का अतिक्रमण पूर्व में हटाया था तथा उसने पुनः अतिक्रमण कर लिया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्त के विरुद्ध अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली का अवलोकन करने व बहस अपीलान्त सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्त अतिक्रमी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है वह उचित है परन्तु प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अपीलान्त को अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्त यदि सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करादे एवं 15 दिवस की अवधि में कब्जा हटाले तो सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय का सिविल कारावास का आदेश भी यथावत रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद

